



मैंने अपने जीवन में एक भी दिन काम नहीं किया। ये सब मनोरंजन था।

-थॉमस ए. एडीसन

मूल्य

₹ 3/-



सांध्य दैनिक

4 PM

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork [@Editor_SanjayS](https://www.youtube.com/4pmNEWSNETWORK)

• तर्फ़: 11 • अंक: 28 • पृष्ठ: 8 • लखनऊ, यूक्राव, 28 फरवरी, 2025

जिद...सच की

चैंपियंस ट्रॉफी: पाकिस्तान का सफर नौ दिन... 7 | अभिषेक व शिवकुमार ने बढ़ाया... 3 | भीड़ का उचित प्रबंधन नहीं करने... 2

थी लैंगेज फार्मूला दक्षिण राज्यों में बढ़ा रहा है बीजेपी की मुसीबत तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने किया आर-पार की लड़ाई का आगाज

» तेलंगाना और कर्नाटक में
भी सुलग रही है आग
» बीजेपी ने भी पूछे सवाल
□ □ □ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने वीडियो जारी कर मोदी सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत थी लैंगेज फार्मूले का मरते दम तक विरोध करने का एलान किया है। तमिलनाडु से पहले कर्नाटक, पंजाब और तेलंगाना से भी विरोध के स्वर फूट चुके हैं।

स्टालिन ने तमिलनाडु की जनता से इस मुद्रे पर मदद की गुहार लगाई है। थी लैंगेज फार्मूले का सबसे ज्यादा विरोध के राज्यों से हो रहा है। गौरतलब है कि यदि यह विरोध तेज होता है और इसे जनता का समर्थन मिलता है तो बीजेपी के लिए यह बड़ी साबित होगा।

क्या है थी लैंगेज फार्मूला

केंद्र की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत शैक्षक प्रणाली में भाषाई संबुद्ध स्थापित करने के लिए त्री-भाषा नीति अपनाई गयी है। इस नीति का उद्देश्य छात्रों को तीन भाषाओं में शिक्षित करना और भाषाई विविधता को प्रोत्साहित करना है। त्री-भाषा नीति का तात्पर्य तीन भाषाओं के अध्ययन से है, जिनमें से एक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, दूसरी हिंदी (गैर-हिंदी भाषी राज्यों में) और तीसरी अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा हो सकती है।

केन्द्र हम पर भाषा युद्ध थोप रहा है : स्टालिन

सीएम एमके स्टालिन ने थी लैंगेज फार्मूले को सबसे बड़ी चुनौतियों करार दिया है। उन्होंने इसे भाषा युद्ध की संज्ञा दी है और कहा है कि हम इस युद्ध में पहले ही काफी कुछ खो चुके हैं। यह हम पर थोप नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि यह संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को हमारे राज्य की रक्षा के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। तमिलनाडु के सीएम ने केंद्र सरकार पर सम्मान बोला। उन्होंने कहा, आज हम कर्नाटक पंजाब, तेलंगाना और अन्य जगहों से एकजुटता की आवाज उठाए हुए देख रहे हैं। इस प्रतिरोध का सामना करते हुए, केंद्र सरकार जोर देकर कहती है कि वह अपनी इच्छा हम पर नहीं थोप रही है, फिर भी उनके सभी कार्य इसके विपरीत संकेत देते हैं। उनकी त्री-भाषा नीति के कारण पहले ही हमने नुकसान उठाया है। हम तमिलनाडु के कल्याण और भविष्य के साथ किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए समझौता नहीं करेंगे। तमिलनाडु विरोध करेगा,

तमिलनाडु विजयी होगा।

थी लैंगेज फार्मूला धीरे-धीरे सियासत में हवा के रूख को बदल रहा है। एनडीए और इंदिया गतिविधि दोनों ही इसका फायदा और नुकसान अपने-अपने हिसाब से देख रहे हैं। दक्षिण के राज्यों में बड़ी मुश्किल से बीजेपी को सफलता हासिल हुई है। ऐसे में यदि यह लड़ाई हिंदी बनाम



लगातार हो रहा है विरोध

हिंदी को अनिवार्य करने के प्रयासों का कई राज्यों में विरोध होता रहा है। यह विवाद विशेष रूप से दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर राज्यों और बंगाल जैसे क्षेत्रों में अधिक तीव्र रहा है, जहाँ क्षेत्रीय भाषाएं न केवल संघर्ष का मात्राम है, बल्कि सांस्कृतिक पह्यान का प्रतीक भी मानी जाती है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 1950 में मिला, लेकिन इसे राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य करने के प्रयासों का विरोध शुरू से ही रहा। तमिलनाडु में 1965 का हिंदी विरोधी अंदोलन इसका प्रमुख उद्घारण है। इसी प्रकार, केरल, बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी संघर्ष-सामन्य पर हिंदी की ओरपे के प्रयासों का विरोध हुआ है। क्षेत्रीय भाषाओं के समर्थकों का तरह है कि प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा और संस्कृति है, जिसे



संरक्षित किया जाना चाहिए। एक स्पष्ट कानून है कि यह देश की भाषाएं बहुलता के बिलाफ हैं और इससे गैर-हिंदी भाषी राज्यों में असोश बढ़ सकता है। इस विवाद का समाधान बहुमानिकता को बढ़ावा देने ने है। सरकार को दिली के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं को भी समान महत्व देना चाहिए ताकि भाषाई सौराहत बना रहे और सभी समुदायों की पह्यान सुरक्षित रहे।

प्रिक्षकों की कमी

सरकार द्वारा लागू की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्राणी रूप से लागू करने में योग्य शिक्षकों की भारी कमी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। एनईपी के तहत प्रायोगिक स्तर पर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। हालांकि, सभी भाषाओं के लिए प्रशिक्षित और योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। विशेष रूप से आदिवासी और दूसरों के क्षेत्रों में दिशित और नींगमी है, जहाँ स्थानीय भाषाओं में शिक्षण के लिए उपचुक शिक्षक निलंबित होता है। इसी तरह, विज्ञान, गणित और तकनीकी विषयों के लिए भी शिक्षकों की कमी बनी हुई है।

हिंदी बनाम अदर लैंगेज

क्षेत्रीय भाषा के तौर पर विकसित होती है तो इससे बीजेपी को राजनीतिक नुकसान हो सकता है। स्टालिन ने बड़ी खुबसूरती से इस मुद्रे को

राजनीतिक मुददा बना दिया है। उन्होंने हिंदी पर आरोप लगाये हैं कि वह दर्जनों क्षेत्रीय भाषाओं को निगल चुकी है। स्टालिन ने एक स्तर पर लिखा

कि भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमाऊँनी, मगाई, मारवाड़ी, मालवी, छत्तीसगढ़ी, संथाली, अगिका, हो, खड़िया, खोरात, कुरमाली, कुरुख, मुंडारी और कई अन्य भाषाएं अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। इन भाषाओं का बुरा हाल हिंदी के कारण है।

हिंदी को लेकर स्टालिन की टिप्पणी समाज को बांटने का ओछा प्रयास : वैष्णव

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अधिनी वैष्णव ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को “हिंदी थोपने” संबंधी टिप्पणी को उनकी सरकार के खराब शासन को छिपाने के लिए समाज को बांटने का “ओछा प्रयास” बताया और सवाल किया कि क्या कांग्रेस नेता



सहमत हैं। वैष्णव ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “यह जानना दिलचस्प होगा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का इस विषय पर क्या कहना है। क्या वह हिंदी भाषी क्षेत्र की सीट के सांसद के रूप में इससे सहमत

है। उत्तर भारतीय राज्यों में बीजेपी को इस फार्मूले से क्या फायदा मिलेगा। क्योंकि स्टालिन के विरोध के बाद बीजेपी ने सीधा सवाल राहुल गांधी से पूछा है कि उनके मित्र स्टालिन हिंदी का विरोध कर रहे हैं। उनका क्या कहना है?

अखिलेश कर चुके हैं विरोध

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस नई व्यवस्था का विरोध कर चुके हैं। छात्रों द्वारा संसदीय सत्र के दौरान जंतर-मंतर पर किये गये विरोध प्रदर्शन में भी अखिलेश यादव ने हिस्सा लिया था। और छात्रों को भरोसा दिलाया था कि वह उनके साथ है।



भीड़ का उचित प्रबंधन नहीं करने से महाकुंभ में आई आपदा : अजय राय

- » योगी सरकार पर जमकर बरसे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष
- » कहा- जनता की सुरक्षा से ज्यादा 'वीआईपी' लोगों को प्राथमिकता दी गई
- 4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी और भाजपा पर करारा वार किया है। उन्होंने महाकुंभ में कथित कुप्रबंधन को लेकर योगी अदित्यनाथ सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता की सुरक्षा से ज्यादा अति विशिष्ट लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। यहां लहुवारीर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में राय ने कहा, कुंभ में भगदड़ दिल दहला देने वाली थी, लेकिन यह सरकार की वीआईपी संरक्षित का नहीं जाना थी।

पूरा प्रशासन अति विशिष्ट लोगों की सुविधा में व्यस्त था, जबकि आम श्रद्धालुओं को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। भीड़ का उचित प्रबंधन नहीं किया गया और इस लापरवाही के कारण आपदा आई। उधर राज्य सरकार और कई मंत्रियों ने बुधवार को संपन्न हुए कुंभ में कुप्रबंधन के आरोपों का कई मौकों पर खंडन किया है। राज्य सरकार ने पलटवर



सीएम ने दिखाई असरेनाईलता

हजारों लोग अपने प्रियजनों के लिए शोक मना रहे थे, और फिर भी योगी अदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने में व्यस्त थे। अगर यह असरेनाईलता नहीं है, तो वह क्या है?" राय ने कहा कि कुंभ में इयूटी के दैयन नामे गए गानीपुर के इंस्पेक्टर अंजली कुमार राय को सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'अगर सरकार कुंभ का प्रबंधन करने वालों को सम्मानित कर रही है, तो सेवा में अपना जीवन देने वाले इंस्पेक्टर को क्यों नहीं? उनका बलिदान सम्मान का हकदार है।' राज्य के अधिकारियों ने पहले कहा था कि राय उस वक्त कुंभ इयूटी पर नहीं थे। राय ने महाशिवरात्रि शिव बायात जुगूस के आरंभिक स्थगन पर भी नाराजगी जताई और इसे धार्मिक पर्याप्ती पर हमला बताया।

यूपी में कांग्रेस करेगी 600 समाएं

मतदाताओं से जुड़ने के लिए कांग्रेस ने नई राजनीति अपनाई है। इसके लिए पार्टी हर विधानसभा थेट्रो में मतदाता जोड़े गए अनियान घलाएगी। विधानसभा क्षेत्रों में 100 दिन भी कारीब 600 समाएं आयोजित कर एक लाख लोगों से संकल्प पर भरवाए जाएंगे। इसकी शुरुआत आज जगह के निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से 28 फरवरी से हो रही है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से मैटान में जुड़ी है। पार्टी यह चुनाव सपा अथवा अन्य दलों से मिलकर लड़नी या नहीं, यह तय बोला बाकी है, लेकिन पार्टी मतदाताओं को शुद्ध से जोड़ने के लिए एकी-योटी का जोर लगा रही है। इसी राजनीति के तहत यह मुहिन शुरू की जा रही है। नमस्ते निजामाबाद के नाम से शुरू होने वाले इस गण अनियान की निजमादी पार्टी के निवर्गान प्रदेश संगठन महाशिवर अनिल यादव को सौंपी गई है। गण अनियान ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ईजगार, सामाजिक व्याय, जातीय जनगणना और संविधान सुरक्षा के मुद्दे पर हर गांव पंचायत में नीति समाएं होनी। इस तरह पूरे विधानसभा क्षेत्र में 500 से 600 समाएं होंगी। इस दौरान एक लाख से अधिक लोगों से संकल्प पर भरवाया जाएगा। 51 सदस्यों की निजामाबाद एवं शन करेटी भी बनाई जाएगी।

करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दलों पर निशाना साधा और उन पर अपनी टिप्पणियों से सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी है और सदियों से

शिव बारात एक पवित्र परंपरा रही है। प्रशासन को इसे बदलने का अधिकार किसने दिया? जनता के व्यापक आक्रोश के बाद ही उन्हें मूल तिथि को बहाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बुलाई बैठक

- 4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को दिल्ली की कानून-व्यवस्था के मुद्दों को लेकर बैठक कर रहे हैं यह बैठक सुबह 11 बजे से शुरू हुई है।

दिल्ली में होने वाली इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह विभाग के मंत्री आशोष सूद के साथ दिल्ली पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में मुख्य रूप से महिला सुरक्षा और बांगालदेशी घुसपैठियों को लेकर चर्चा की जाएगी।

शीला दीक्षित की सरकार के बाद ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है, जब केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली की मुख्यमंत्री सहित कई गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के

रुक... चार दिन से एक ही सवाल पूछ रहा है..... झाड़ू फिरे....

ब्रह्मलक्ष्मि
रंग इन्हें



पूर्व सांसद बृजभूषण पर लगा आपराधिक मुकदमा वापस

- » हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अर्जी पर लिया फैसला
- 4पीएम न्यूज नेटवर्क

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे को समाप्त कर दिया। यह फैसला राज्य सरकार की उस अर्जी पर आया, जिसमें मुकदमा वापस लेने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की इस अर्जी को मंजूर कर लिया।

दरअसल, निचली अदालत ने सरकार के मुकदमा वापसी के प्रार्थना पत्र को पहले खारिज कर दिया था,



लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत के इस आदेश को भी रख कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने बृजभूषण की याचिका पर सुनाया। यह मामला वर्ष 2014 का है, जब गोंडा जिले की नगर कोतवाली में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और 341 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन करते हुए लोक सेवक के आदेश की अवहेलना की थी।

बद से बदतर हो गई है प्रदेश की कानून व्यवस्था : अवधेश प्रसाद

- » सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, महिला अपराधों सांहित कानून व्यवस्था पर योगी सरकार को धेरा
- 4पीएम न्यूज नेटवर्क



अयोध्या। सपा ने यूपी की भाजपा सरकार पर जमकर वार किया। सूरे के सबसे बड़े विपक्षी दल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी पर निशाना साधा। इसी सिलसिले में सपा ने राज्य में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। राजनारी अयोध्या में भी सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों पर एकत्र हुए। प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया। इस मौके पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया गया।

सपा सांसद ने आरोप लगाया कि अयोध्या में दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। इधर एक-दो महीने में एक दर्जन से अधिक बेटियों के साथ जब्तवाली के शहनवा गांव में बेटी के साथ क्रूरता के साथ हत्या हुई। इस हत्या में भाजपा के लोग फैसे हुए हैं। खंडासा थाना के कुरावन गांव में 14 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ। थाना इन्यातनगर क्षेत्र से एक बेटी स्कूल में फौस जमा करने आई थी। आरोपियों ने उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया और जब वह बेहोश हो गई तो उसे जिला अस्पताल में भर्ती कर फरार हो गए। इसी तरह से थाना पूराकलंदर क्षेत्र के सरियावां में भर्ती चौकीदार की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इन्यातनगर थाना क्षेत्र के परशुरामपुर सथरा में एक व्यक्ति को मार दिया गया। जनपद में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। कानून व्यवस्था संभालने में भाजपा सरकार के लिए सांबित हो रही है।

कांग्रेस को बदनाम कर रही भाजपा : अशोक गहलोत

- » बीजेपी सिर्फ दलितों के नाम पर दाजनीति करती है : जूली



मुख्यमंत्री के साथ नहीं बैठता गया। इस बार साथ बिद्यावा तो गया, लेकिन बोलने नहीं दिया। इसके अलावा, जूली ने फोन टैपिंग मामले पर सीएम को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल नींगा के आरोपों पर गृह राज्य नींगी उनी दिन जबाब दे देते तो गतिशील नहीं बनता। लेकिन सरकार की लापत्ती के कारण यह गृह युद्ध खिंचता रहा।

टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस हमेशा दलितों को संक्षेप बनाने के लिए काम करती रही है, जबकि बीजेपी केवल दियावे की दाजनीति करती है। उन्होंने बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल उतारे हुए कह कि जनता को गुमाय ह करने का काम किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पूरी मजबूती से जनता की आवाज उठाई रही।

को लेकर राज्य मंत्री अविनाश गहलोत की कथित दादी टिप्पणी को सेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हर गतिरोध का अंत समझौता है। हमारे दरवाजे खुले हैं।

R3M EVENTS
ACTIVATION · EVENTS · EXHIBITION

R3M EVENTS
4/725 Vaibhav Khand, Gomti Nagar, Lucknow
E-mail: rajendra@r3mevents.com, Mob : 095406 11100

अभिषेक व शिवकुमार ने बढ़ाया सियासी पारा !

- » भाजपा में जाने को लेकर चर्चा तेज
- » दोनों नेताओं ने इन खबरों का किया खंडन
- » दोनों ने अपनी पार्टियों में दिल्ली आस्था

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। आजकल सियासत में किसी से मिलना भी राजनीतिक लोगों के लिए दुश्यार हो गया है। अगर कोई विपक्षी नेता सत्ता पक्ष के किसी नेता के कार्यक्रम में पहुंच जाए तो और बावाल में चम्प जाता है। देश के दो बड़े राज्यों परिचम बंगाल व कर्नाटक को लेकर ऐसा की कोहराम मचा हुआ। जहां कर्नाटक में एक कार्यक्रम में कांग्रेस सरकार के डिप्टी सीएम शिवकुमार के बैंगलुरु के एक कार्यक्रम में पहुंचे जहां पर गृहमंत्री अमित शाह भी थे। इसको लेकर अटकलें बढ़ी की वह भाजपा में जा रहे हैं हालांकि उन्होंने इससे इंकार कर दिया।

उधर कुछ इसी तरह की चर्चा बंगाल में भी हो रही हैं टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी भाजपा में जा रहे हैं। इस खबर को भी सांसद अभिषेक ने खारिज कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस की बैठक में अभिषेक बनर्जी ने खुद को लेकर चल रहे अफवाह पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि मैं भाजपा में शामिल हो रहा हूं वे झूँझू फैला रहे हैं। मैं तृणमूल कांग्रेस में गदारों को बेनकाब करता रहूँगा, जैसा कि मैंने विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। अभिषेक बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि मैं तृणमूल कांग्रेस का निष्ठावान सिपाही हूं, मेरी नेता ममता बनर्जी हैं।



26 के लिए हमें तैयार रहना होगा : अभिषेक

तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक ने कहा कि ममता बनर्जी ने कहा कि दो-तिहाई सीटें जीतनी चाहिए। यानी 196, लेकिन मैं कहूँगा कि 214 टॉप वह

जगह है जहां हमें जाना चाहिए। अभिषेक ने यह भी कहा, मतदाता सूची का काम हो चुका है। मतदाता सूची में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। 26 के लिए हमें इसके लिए

तैयार रहना चाहिए। किसी के काल करने और निर्देश देने के इंतजार में न बैठे रहें। जो लोग टीम से प्यार करते हैं, उन्हें खुद ही मैदान में उतरना होगा।

मैं जन्मजात कांग्रेसी, बीजेपी में जाने का सवाल ही नहीं : डीके शिवकुमार

कर्नाटक में उपमुख्यमंत्री शिवकुमार के एक कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर सियासी बवाल मच गया है। लोगों ने क्यास लगाना शुरू कर दिया है कि वह भाजपा में जा रहे हैं हालांकि उन्होंने इसका खंडन कर दिया है। बता दें कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने पहले प्रयागराज महाकुंभ में सान किया और फिर यूपी की योगी सरकार की तारीफ की। इसका बाद वह महाशिवरात्रि के उत्सव पर सुरु जग्गी यासुदेव के ईश योग सेंटर में गए। इस कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए थे। इसका बाद से अटकलें लगाई जा रही हैं कि डीके शिवकुमार भी अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं जन्म से ही कांग्रेसी हूं, महाकुंभ में मेरी आस्था है और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, ऐसी अटकलें मेरे करीब भी नहीं फटकतीं। मैं बीजेपी के आरोपों को गंभीरता से नहीं लेता।

मीडिया से बात करते हुए कहा, ईशा फाउंडेशन आने के लिए मेरी पहले ही आलोचना हो चुकी है। मुझे सदस्युर ने आमंत्रित किया था, इसलिए मैं यहां आया। मैं जन्म से हिंदू हूं, जो सभी धर्मों से प्यार करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बीजेपी के करीब आ रहा हूं, लेकिन मैं अमित शाह से भी नहीं मिला हूं। डिप्टी सीएम ने कहा कि मैंने मीडिया और सोशल मीडिया में देखा है और मेरे दोस्त भी फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या मैं बीजेपी के करीब आ रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जन्म से ही कांग्रेसी हूं, महाकुंभ में मेरी आस्था है और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, ऐसी अटकलें मेरे करीब भी नहीं फटकतीं। मैं बीजेपी के आरोपों को गंभीरता से नहीं लेता।

नौकरी घोटाले में नाम आने पर बगाल में सियासत तेज

दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में बुधवार को राजनीतिक गलियारों में उस समय हलचल मच गई, जब यह बात सामने आई कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने “रक्कूल में नौकरी घोटाला” मामले में दाखिल तीसरे पूरक आरोपण पर मैं किसी अभिषेक बनर्जी का नाम लिया है। एंजेसी ने आरोपण पर 2017 में रिकॉर्ड एक बातचीत की ओँडियो फाइल का हवाला दिया और

उमर के बयान से गरमाई जम्मू-कश्मीर की सियासत

- » अनुच्छेद 370 के बाद हालात में सुधार की बात कह कर फँसे
- » विपक्ष ने किया तीखा हमला
- » आरोपों का सिलसिला जारी
- » पीड़ीपी व कांग्रेस ने भी घेरा

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में चुनाव से पहले और चुनाव के बाद राजनीति बहुत बदल गई है। जहां कांग्रेस व नेंका ने मिलकर चुनाव लड़ा था पर चुनावों में जब नेंका को पूर्ण बहुमत मिला तो कांग्रेस के साथ उसकी दूरी बढ़ गई। अब सरकार बनने के बाद भाजपा की केंद्र की सरकार के साथ जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखा शायद इसमें उनकी मंशा राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा से मदद लेने की रही होगी।

वहीं अब धारा 370 के फेवर बोल कर वह सियासी कोहराम मचा कर अपने को आलोचनाओं के तीर पर पहुंचा दिया है। विपक्ष तो उनको भाजपा के आगे झुकने का अरोप लगा रहे हैं पर उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ मिलकर काम करना और भाजपा की राजनीति को स्वीकार करने में बड़ा अंतर है। कुछ



आपका समर्थन अब कर्मीरियों के खिलाफ कठोर रुख अपनाने के अलावा और कुछ नहीं : वहीद पर्दा

पीड़ीपी नेता एवं विधायक वहीद पर्दा ने एकस पर लिखा, प्रिय उमर अब्दुल्ला साहब, चूंकि आप अब शांति का समर्थन कर रहे हैं- अगर आज कश्मीर में शांति दिख रही है, तो इसकी वजह

और संपत्तियों की कुर्की, सत्यापन, कड़े कानूनों के तहत कैदियों को बाहर रखना और कर्मियों को नौकरी से निकालना है। यह

आपके चुनाव अभियान व घोषणापत्र से पूरी तरह उलट है। आपका समर्थन अब कर्मीरियों के खिलाफ कठोर रुख अपनाने के अलावा और कुछ नहीं है। पर्दा ने आगे लिखा, अगर आज अलगावादी गतिविधि नहीं है, तो

इसकी वजह अलगावादीयों के खिलाफ कड़े कदम, हुरियत और जमात पर प्रतिबंध है। अगर मीरवाइज को सुरक्षा दी गई है, तो यह उनकी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि इसलिए है, क्योंकि उनकी कमज़ोरी बढ़ गई है।

सीएम जिम्मेदार पद पर बैठे हैं ऐसी टिप्पणी न करें : उमर फारूक

जो एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं और समझदारी से बात करते हैं। उनकी ओर से मीरवाइज को दी गई सुरक्षा के पीछे मकसद बताते हुए और परिस्थितियों को जानते हुए भी बैठुकी टिप्पणी बेदह खेदजनक है। इस तरह की गैरजिम्मेदाराना टिप्पणियों से टिप्पणीकारों की असुरक्षा और मानसिकता के बारे में पहले से ही परेशान व दमित लोगों के बीच अधिक मोहब्बत होता है।



और भी बहुत कुछ देखने के लिए, तैयार हो जाइए : लोन

जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने भी एकस पर लिखा, सीएम साहब कोई भावना न दिखाते हुए अपनी बात छिपाने की काशिश कर रहे हैं। मैं 370 हटाने के लिए अनिच्छा से मौन समर्थन पर आश्वर्यविकृत नहीं हूं। यह उनके लिए वोट करने वालों के लिए सिर्फ ट्रेलर है। फिल्म अभी शुरू होनी है। और भी बहुत कुछ देखने के लिए तैयार हो जाइए।



में सुधार की बात कही है। इससे जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक गलियारों में हलचल आ गई है। उमर के इस बयान को लेकर विपक्षी दल पीड़ीपी ने आलोचना की है, वहीं, मीरवाइज उमर फारूक ने भी सवाल उठाए हैं।

शराब जीवन और परिवारों के बर्बाद कर रहा है : इलिंजा

पीड़ीपी नेता इलिंजा मुपूरी ने लिखा कि शराब और इनस जम्मू-कश्मीर में जीवन और परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा धारा 370 हटाने के बाद इसकी वजह हुआ है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें इसे खत्म करने के लिए एक साथ आने वाले हैं। इलिंजा मुपूरी ने कहा कि हम जब बहुत ही गोली मारे पर पर्याप्त करने आए हैं। जम्मू-कश्मीर में इनस और शराब का मुद्दा आग की तरह खड़ा हो गया है। कुपाइना से हांगे विधायक फैजायना में एक विधेयक पैश किया है। उज्जैने कहा कि जम्मू-कश्मीर के बैद्युतीय नाम जीवन और शराब की ओर जा रहे हैं। हम लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं। नशीली दलों के खिलाफ और लोगों से हांगा। इलिंजा मुपूरी ने कहा कि जैनता से अनुरोध करती हूं कि वे जगते अभियान में हमारे साथ आए। पिछले 4-5 वर्षों से, जम्मू-कश्मीर पुलिस नशीली दलों के खिलाफ लोकों के लिए बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैं उज्जैने अल्पोद्ध करती हूं कि वे जम्मू-कश्मीर में गुरुत उपलब्ध शराब पर शेष लगाए।



Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma

@Editor_Sanjay

जिद... सच की

शिक्षकों और विशेषज्ञों की कमी दूर करनी होगी

पूरे देश में फाइनल परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। खासतौर पर बोर्ड की परीक्षाओं के समय छात्र दबाव में आ जाते हैं। माता-पिता के साथ अध्यापक भी बच्चों पर दबाव बनाने लगते हैं कि वह बोर्ड परीक्षाओं के लिए मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल करें। ये कुल मिलाकर उचित नहीं हैं इससे बच्चे परीक्षा के समय तनाव में आकर अपनी परीक्षा को गलत कर जाते हैं और बाद में कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। कुल मिलाकर ऐसा माना जा रहा है कि प्रशिक्षित शिक्षकों और विशेषज्ञों की कमी भी बड़ी बाधा बन रही अच्छे बच्चों के भविष्य के लिए। वहीं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 ने खेल और शारीरिक शिक्षा को महत्व दिया है, लेकिन इसे अब भी एक वैकल्पिक विषय के रूप में देखा जाता है प्रशिक्षित शिक्षकों और विशेषज्ञों की कमी भी खेल शिक्षा के विकास में एक बड़ी बाधा बनी हुई है।

चूंकि खेल विज्ञान और खेल प्रबंधन अपेक्षकृत नए क्षेत्र हैं, इसलिए इन विषयों में योग्य शिक्षकों और विशेषज्ञों की उपलब्धता सीमित है। इससे विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण और शिक्षण प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसे मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित करने की सख्त आवश्यकता है ताकि विद्यार्थियों को खेल और शारीरिक शिक्षा में अधिक अवसर मिल सकें और इस क्षेत्र को एक सम्मानजनक करियर विकल्प के रूप में देखा जाए। जब तक खेल क्षेत्र को मुख्यधारा में स्थान नहीं दिया जाएगा और इसे अन्य विषयों के समकक्ष नहीं माना जाएगा, तब तक खेल क्षेत्र में दीर्घकालिक प्रगति करना मुश्किल होगा। भारत में खेल शिक्षा को संगठित और प्रभावी बनाने के लिए एक केंद्रीय नियामक निकाय की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। इस दिशा में राष्ट्रीय खेल शिक्षा परिषद जैसे निकाय की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यह निकाय देशभर के खेल और शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को मानकीकृत करने के साथ-साथ खेल विज्ञान, खेल प्रबंधन, खेल योग्यता और खेल मनोविज्ञान जैसे विषयों के लिए एक समग्र नीति विकसित कर सकता है। इसके अलावा, शारीरिक शिक्षकों और खेल विशेषज्ञों के लिए प्रमाणन और लाइसेंसिंग की एक व्यवस्थित प्रक्रिया तैयार की जा सकती है, जिससे इस क्षेत्र में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण और प्रशिक्षण सुनिश्चित हो सके। ग्रामीण स्तर पर हालांकि शारीरिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए सेना व पुलिस की भर्तियों में गांवों के परीक्षार्थी ज्यादा संख्या में दिखाई देते हैं। अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) को बढ़ावा देकर खेल शिक्षा में नवाचार और आधुनिक तकनीकों का समावेश किया जा सकता है।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

विश्वनाथ सचदेव

भूल जाना आदमी की फितरत है। आदमी अच्छी बातें भी भूल जाता है, और बुरी बातें भी। बुरी बातों को भूल जाना तो अच्छी बात है, पर कुछ अच्छी बातों को भूल जाना अच्छा नहीं है। ऐसी ही अच्छी बात वर्ष 1965 की भारत-पाक लड़ाई है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को मात दी थी। पता नहीं कितनों को याद होगा कि उस लड़ाई में अब्दुल हमीद नाम का एक भारतीय सैनिक भी था, जिसने पाकिस्तानी टैक्सों को नष्ट करके हमारी जीत को संभव बना दिया था। तब क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद ने हमें जिता तो दिया, पर अपनी जान की कीमत देकर। कृतज्ञ राष्ट्र ने उस जांबाज शहीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया था।

इस शहीद का जन्म उत्तर प्रदेश के दुल्लहपुर नामक गांव में हुआ था। गांव वालों ने अपने इस सपूत्र के सम्मान में गांव के स्कूल का नाम वीर अब्दुल हमीद उच्च प्राथमिक विद्यालय रखा था। बरसों से यह नाम गांव की एक पहचान बना हुआ था। कुछ ही अर्सा पहले स्कूल का नाम बदल दिया गया- नया नाम पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय धामपुर कर दिया गया। वर्षों बदला गया, किसी ने नहीं बताया। बस बदल दिया! नाम बदलने की यह अकेली घटना नहीं है। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मऊ को जोड़ने वाली सड़क पर बने एक द्वार का नाम ऐसे ही बदल दिया गया था। बिगेडियर मोहम्मद उस्मान के नाम का यह द्वार बुलडोजर चला कर गिरा दिया गया। मुख्तार अहमद अंसारी के नाम पर बने एक कॉलेज की दीवारें गिरा देने वाला समाचार भी हाल ही का है। यह बात भुला दी गयी कि मुख्तार अहमद अंसारी कभी कांग्रेस पार्टी

नेताओं को बौना बना रही है संकीर्णता

के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आजादी की लड़ाई के दौरान यह पद संभालने वाले अंसारी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की नींव रखने वालों में थे। नाम बदलने का यह सिलसिला अब नया नहीं लगता। चाँकाता भी नहीं। पिछले दो दशकों में न जाने कितनी जगह के नाम बदले गये हैं। ज्यादातर नाम मुसलमानों के हैं। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलता। औरंगजेब ने भले ही अत्याचार किये हों, पर वह वर्षों तक इस देश में शासन करता रहा, यह हकीकत तो अपनी जगह है। फिर, हम क्यों भूल जाते हैं कि किसी औरंगजेब को याद करने का मतलब उन अत्याचारों की भी याद दिलाता है, जिनसे हमारे इतिहास के पत्रे भरे हुए हैं। ऐसी बातों को याद रखना इसलिए भी जरूरी है कि इन्हें दुर्बार्या न जाये। बहरहाल, जगहों के नाम बदलना कोई नयी बात नहीं है। पर इस प्रक्रिया के पीछे की मानसिकता को भी समझा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शहरों आदि के नाम बदलने का काम सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में ही हो रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, द्रमुक आदि



पार्टीयों ने भी अपने-अपने शासन काल में इस तरह नाम बदलते हैं। सच्चाई यह है कि अक्सर यह बदलाव राजनीतिक स्वार्थ का परिणाम होते हैं। अपने-अपने हितों के लिए हमारे राजनीतिक दल अक्सर जगहों का नाम बदलना एक आसान मार्ग समझ लेते हैं। लेकिन, यह आसान मार्ग अक्सर राष्ट्रीय हितों से भटका देता है, इस बात को भुलाना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसे कीटों पर भी पड़ता है, जिससे यह जंगल का नुकसान हुआ। आमतौर पर, एक चिनार 30 मीटर (98 फीट) या उससे अधिक तक बढ़ता है, और अपनी दीर्घायु और फैले हुए मुकुट के लिए जाना जाता है।

पेड़ों को अपनी परिपक्व ऊंचाई तक पहुंचने में लगभग 30 से 50 साल लगते हैं और उन्हें अपने पूर्ण आकार तक बढ़ने में लगभग 150 साल लगते हैं। कश्मीर के बन विभाग की 2021 की एक पुस्तिका के अनुसार, कश्मीर में चिनार के पेड़ों की संख्या में गिरावट आई है। जंगल कम होने से कस्तूरी मृग और अनंतनाग जिले के मशहूर अचाबल तालाब में तली दिख रही है। कभी इससे 15 गांवों को पानी की आपूर्ति और कई सौ एकड़ धान के खेतों की सिंचाई होती थी। अनंतनाग जिले में वेरीनाग स्त्रोत में पानी का बहाव बहुत कम हो गया है। वेरीनाग से झेलम नदी निकलती है, जो घाटी के बीच से अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, गांदरबल, बादीपोरा और बारामूला जिलों तक बहती है और फिर पाकिस्तान के मिथनकोट में संधु नदी में मिल जाती है। संधु में मिलने से पहले, झेलम और रावी चेनाब नदी में मिलती हैं। समझा जा सकता है कि झेलम की धार कमज़ोर होने का अर्थ है कि कश्मीर में भयानक जल संकट। इससे भी बड़ा संकट है जमीन और जंगलों के शुक्र होने का। यह जंगल

खतरे में है कश्मीर की नैसर्गिक अस्मिता

पंकज चतुर्वदी

बीते कुछ सालों में कश्मीर घाटी के मौसम में बदलाव यहां के नैसर्गिक पर्यावरण के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। आमतौर पर 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक कश्मीर घाटी में चिलई कलां के दौरान तापमान शून्य से नीचे और भारी बर्फबारी होती है। मौसम विज्ञानियों ने भविष्यवाणी की थी कि 2024-2025 में ला नीना प्रभाव के कारण इस क्षेत्र में अच्छी बरसात होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। न बर्फ गिरा और न ही बरसात। मौसम विभाग ने पहले ही कश्मीर घाटी में जनवरी के महीने में 81 प्रतिशत कम बारिश होने के चलते अलर्ट जारी किया है। कुटुंब में पिछले करीब तीन माह के दौरान क्षेत्र में इस बर्फ पर्यावरण अस्तित्व हुई है। जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित हुई है क्योंकि केसर की खेती। बेमौसम गर्मी के कारण न तो उसकी जड़ों का विस्तार हो पहुंचा है और न ही पौधे की वृद्धि। कम बर्फबारी

की आग का बड़ा कारक होता है। वैसे भी कश्मीर में जंगल साल दर साल कम हो रहे हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में, जम्मू और कश्मीर ने 112 हेक्टेयर प्राकृतिक वन को खो दिया। वर्ष 2020 में, इस क्षेत्र में 1.15 मिलियन हेक्टेयर प्राकृतिक वन था, जो इसके भूमि क्षेत्र का 11 प्रतिशत था। हालांकि, इस क्षेत्र में जंगल में आग की घटनाओं में इजाफा हुआ है और इसका मूल कारण भी कम बर्फबारी से उत्पन्न शुक्र परिवेश है। वर्ष 2001 और 2023 के बीच, जम्मू और कश्मीर में आग लगने से 23



का सबसे दूरगामी कुप्रभाव है यहां की जल निधियों का अभी से सूखना। गांदरबल जिले की कई सरिताएं और छोटी नदियां अब सूख चुकी हैं। अनंतनाग जिले के मशहूर अचाबल तालाब में तली दिख रही है। कभी इससे 15 गांवों को पानी की आपूर्ति और कई सौ एकड़ धान के खेतों की सिंचाई होती थी। अनंतनाग जिले में वेरीनाग स्त्रोत में पानी का बहाव बहुत कम हो गया है। वेरीनाग से झेलम नदी निकलती है, जो घाटी के बीच से अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, गांदरबल, बादीपोरा और बारामूला जिलों तक बहती है और फिर पाकिस्तान के मिथनकोट में संधु नदी में मिल जाती है। संधु में मिलने से पहले, झेलम और रावी चेनाब नदी में मिलती हैं। समझा जा सकता है कि झेलम की धार कमज़ोर होने का अर्थ है कि कश्मीर में भयानक जल संकट। इससे भी बड़ा संकट है जमीन और जंगलों के शुक्र होने का। यह जंगल

प्रतिशत पेड़ों का नुकसान हुआ। आमतौर पर, एक चिनार 30 मीटर (98 फीट) या उससे अधिक तक बढ़ता है, और अपनी

संघ व भाजपा कर रही साजिश

तेजस्वी बोले- नीतीश के बेटे को राजनीति में आने से रोकने की तैयारी

» पीएम ने लगाया था
नीतीश पर भोजन की
प्लॉट छिनने का आरोप

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

पटना। बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद ने भाजपा पर फिर तीखा प्रहार किया। राजद नेता का मानना है कि निशांत के राजनीति में आने से जदयू के विलुप्त होने से बच जाने की संभावना है, जो भाजपा और उसके समर्थकों को परसंद नहीं है। श्री यादव ने कहा, सबसे पहले तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि चाहे निशांत हो या कोई और, राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय व्यक्ति का अपना होना चाहिए। मेरे माता-पिता (पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी) ने मुझे राजनीति में आने के लिए नहीं कहा था।

मैंने बिहार का दौरा करने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता का मूड भाँपते हुए खुद यह निर्णय लिया। यादव ने कहा, “बेशक, अगर वह आगे आते हैं तो पार्टी को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। इसलिए, जदयू में मौजूद संघियों की मदद से भाजपा में कई लोग उनके प्रवेश को रोकने की साजिश में

सीएम के अपमानजनक बयानों से पीएम का सीना हुआ चौड़ा

यादव ने कहा, नीतीश जी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई जब नीतीश जी ने जब राजगंग में नहीं थे, प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच से विधानसभा के गैरिट कुछ टिप्पणी की। अब नीतीश जी भाजपा के

सहयोगी हैं और उनके आमानजनक बयानों से प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच से उन्होंने कहा, विलुप्त हो गया है।

मन बना लिया है। भाजपा यहां सता लायिन नहीं कर पाएगी। लेकिन हम नीतीश जी से अपने ‘पोस्टर बैंग’ बोलकर कोशिश जारी रख सकती है।

लगे हुए हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने बुधवार को मंत्रिमंडल विस्तार को हल्के में लेते हुए कहा कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि यह उन सभी के लिए आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि चुनाव कुछ ही महीने दूर हैं और बिहार के लोगों ने राजगको वोट नहीं देने का मन बना लिया है, जिसने राज्य पर करीब 20 साल तक शासन किया है। उन्होंने हाल ही में भागलपुर

दौरे पर आए बिहार के मुख्यमंत्री पर स्लेह बरसाने के लिए प्रधानमंत्री ने रेन्ड्र

मोदी का मखौल उड़ाया और दोनों नेताओं को पुरानी कटुता याद दिलाई। यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नीतीश जी को लाडला कहा, हालांकि एक बार नीतीश पर भोजन की प्लॉट छिन लेने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कई साल पहले नीतीश द्वारा एक रात्रिभोज को रद करने की घटना का जिक्र किया।

पहले जल्दा को तूना याहते हैं।

महाराष्ट्र में शर्मनाक घटना के बाद सियासी उबाल

पुणे में बस के अंदर महिला का बलात्कार, विपक्ष ने महायुति सरकार को घेरा

» आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे को पुलिस ने दबोचा

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में दिल्ली की निर्भया कांड की तरह एक घटना घटी जिसमें पुणे में बस के अंदर महिला का बलात्कार किया गया है। हालांकि दरिंदा पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे को दबोच लिया। इसको लेकर राज्य की सियासत में उबाल आ गया है।

राज्य के विपक्षी दलों ने भाजपा की

फडणवीस सरकार पर तीखा प्रहार करते

हुए कहा है राज्य की कानून व्यवस्था

बदलत हो गई है।

कंग्रेस, एनसीपी शरद पवार,

यूवीटी शिवसेना ने

कहा है

जबसे

भाजपा की सरकार आई है राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उधर राज्य सरकार ने कहा है कि दोषी को सख्त सख्त सजा दी जाएगी।

आरोपी का पता लगाने के लिए महाराष्ट्र में

विपक्षी गठबंधन की सरकार होती तो भाजपा हंगामा काट देती : दाउत

संजय राजत ने कहा कि अग्र राज्य में विपक्षी गठबंधन मव विकास आघाडी की सरकार होती तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महिला नेता अब तक राज्य मुख्यालय मंत्रालय के बाहर हंगामा कर रही होती। राजत ने महिलाओं के लिए विधी संसदीय विधायिका की भाजपा नीत सरकार की लालकी बहिन योजना का जिक्र करते हुए पूछा, ८८ महीने 1,500 लप्पये देकर यह आपने महिलाओं की आलसमान खरीद लिया है?

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उपमुख्यमंत्री अग्रिम पवार से जवाब मांगना चाहिए जो पुणे के संस्थक कंती नी है। शिवसेना (उत्तरा) नेता ने कहा, यह दिल्ली के निर्मला कांड जैसा



है। सौभाग्य से, महिला बव गई (इस मामले में)। दिल्ली में 2012 में फिजियोथेरेपी की 23 वर्षीय छात्रा, जिसे बाट में 'निर्मला' कहा जाने लगा, के साथ दिल्ली में एक बस में सामूहिक बलात्कार किया गया।

केवल कानून बनाकर ऐसी घटना को नहीं रोक सकते : चंद्रचूड़

पूर्व सीजेआई डीवाइंस चंद्रचूड़ ने कहा कि निर्मला घटना के बाद कानूनों में बहुत सारे बदलाव लिये गए, लालकि, हम केवल कानून बनाकर ऐसी घटना को नहीं रोक सकते। चंद्रचूड़ ने कहा कि समाज पर बड़ी जिम्मेदारी है और इसके अलावा कानूनों का क्रियान्वयन भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए बने कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाना चाहिए। महिलाएं जल्दी नी जाएं उन्हें सुरक्षित मवस्था करना चाहिए। जल्दी है कि ऐसे मामलों में उत्तिर जाय, कड़ी कार्रवाई, त्वरित सुनवाई और सजा जिम्मेदारी है।



भाजपा की सरकार आई है राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उधर राज्य सरकार ने कहा है कि दोषी को सख्त सख्त सजा दी जाएगी।

आरोपी का पता लगाने के लिए महाराष्ट्र में

कई जगहों पर तेरह पुलिस टीमें तैनात की गई थीं। गुरुवार को पुणे पुलिस ने शिरूर तहसील में सधन तलाशी अधियान चलाया, जिसमें खोजी कुत्तों और ड्रोन का इस्तेमाल करके घने गन्ने के खेतों की तलाशी ली गई, जहां गडे के छिपे होने का संदेह था। यह गिरफतारी पुणे में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच हुई है, जिसके चलते अधिकारियों ने शहर भर के परिवहन केंद्रों पर सुरक्षा उपायों को कड़ा कर दिया है।

स्वारंगेट बस स्टेशन से पकड़ा गया आरोपी

पुणे पुलिस ने शुक्रवार को स्वारंगेट बस स्टेशन पर खाली बस के अंदर 26 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने वाले आरोपी को नियतात कर दिया। पुणे पुलिस के जोन 2 के डीसीपी स्मार्टना पाटिल ने एचनाई को बताया, आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे को ओपराइक लप्प से गिरपतार कर दिया गया है। गाडे का नाम पुणे और अहिल्यानगर जिलों में चौरी, डकैती और चौर लौटिंग के आधा दर्जन मामलों में दर्ज है। वह इनमें से एक अपराध के लिए 2019 से जमानत पर बाहर है।

आरोपी के खिलाफ कई आपाराधिक मामले हैं दर्ज

हिंदूरायाट गाडे (37) पर मंगलवार सुबह स्टेट ट्रांसपर्ट (एसटी) बस के अंदर नीत अधिकारी के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को नियतात कर दिया। पुणे पुलिस के जोन 2 के डीसीपी स्मार्टना पाटिल ने एचनाई को बताया, आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे को ओपराइक लप्प से गिरपतार कर दिया गया है। गाडे का नाम पुणे और अहिल्यानगर जिलों में चौरी, डकैती और चौर लौटिंग के आधा दर्जन मामलों में दर्ज है। वह इनमें से एक अपराध के लिए 2019 से जमानत पर बाहर है।

गंगा में डुबकी लगाने से शिंदे का पाप नहीं धूल जाएगा : उद्धव ठाकरे

» शिवसेना नेता व डिप्टी सीएम पर यूवीटी सेना का निशाना

» महाराष्ट्र को धोखा देने वाले न दें सीख

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क



मुंबई। शिवसेना (यूवीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से महाराष्ट्र को धोखा देने का पाप नहीं धूलता। वे हमें सीख न दें। मराठी गौरव दिवस के अवसर पर पार्टी के एक कार्यक्रम में ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि नव-दिनुवादियों को उनकी पार्टी को भगवान राम का महत्व सिखाने की जरूरत नहीं है।

ठाकरे ने शिंदे का नाम लिए बगैर कहा, “मैं गंगा का सम्मान करता हूं, लेकिन 50 खोखे लेने के बाद इसमें डुबकी लगाने का क्या फायदा है। यहां, आप महाराष्ट्र को धोखा

देते हैं, 50 खोखे लेते हैं और फिर डुबकी लगाते हैं। इससे किसी का पाप नहीं धूलता। (गंगा में) कई बार डुबकी लगाने के बाद भी विश्वासघाती होने का ठप्पा कैसे जाएगा। पार्टी में विभाजन के बाद 2022 में शिवसेना (उत्तरा) ने शिंदे और 39 विधायकों पर शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करने के लिए 50 खोखे (प्रत्येक को 50 करोड़ रुपये) लेने का आरोप लगाया थी। शिंदे के विद्रोह के कारण ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार गिर गई।

भाजपा पर भी बदसे पूर्व महाराष्ट्र सीएम

भाजपा पर हमला करते हुए ठाकरे ने कहा कि यह दुर्गमियांपूर्ण है कि देश उन लोगों के हाथों में है जिनका स्वतंत्रता संघात से कोई संबंध नहीं है और राज्य उन लोगों के हाथों में है जिनका संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन से कोई संबंध नहीं था।

थी। शिंदे और शिवसेना विधायक इस सासाह की शुरुआत में महाकुंभ के लिए प्रयागराज गए थे। इससे पहले दिन में शिंदे ने महाकुंभ में शामिल नहीं होने के लिए ठाकरे पर कटाक्ष किया था और कहा था कि ठाकरे खुद को हिंदू कहलाने से डरते हैं। शिंदे ने उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना पत्रकारों से कहा, “जो लोग महाकुंभ में शामिल नहीं हुए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने इसमें हिस्सा क्यों नहीं लिया।

संभल की शाही जामा मरिजद की नहीं हो सकेगी रंगाई-पुताई

» साफ- सफाई कराए जाने की मांग को मंजूरी

» इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

प्रयागराज। संभल की विवादित शाही जामा मरिजद की रंगाई-पुताई की इजाजत की मांग मामले में मरिजद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने मरिजद में साफ सफाई कराए जाने की मांग को मंजूरी दी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।

हालांकि कोर्ट ने अभी व्हाइट वॉश यानी मरिजद की रंगाई-पुताई, मरम्मत और लाइटिंग को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया है। हाईकोर्ट इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद 4 मार्च 2024 को व्हाइट वॉश की तरफ से जी यह कहा गया है कि मरम्मत में पहले से ही पैटिंग है, ऐसे में नए सिरे से पैटिंग कराए जाने की कोई जरूरत नहीं है। एसएसई। इस रिपोर्ट पर मरिजद कमेटी ने कोर्ट में आपत्ति जताई है।

को अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट पेश की। एसएसई की रिपोर्ट में कहा गया है कि मरिजद में पहले से ही पैटिंग है, ऐसे में नए सिरे से पैटिंग कराए जाने की कोई जरूरत नहीं है। एसएसई। इस रिपोर्ट पर मरिजद कमेटी ने कोर्ट में आपत्ति जताई है।

नेपाल में केंद्र, पटना से दार्जिलिंग तक झटके खुल गई। इसके झटके ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक लगभग 6 बार धरती खट्टर की रात नेपाल में 5.5 तीव्रता की भूकंप आया। इसके झटके बिहार और असम तक महसूस किए गए। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप भारतीय समयानुसार रात में 2:36 बजे आया। सुबह 5:14 बजे तीव्रता 4.3 रही। यहां भी किसी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तिब्बत में 27 फरवरी की दोपहर 2:48 बजे 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसके कुछ घंटे बाद शाम 5:10 बजे स्थानांतर में लोगों में भूकंप के झटके महसूस किए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.2 रही।

आइटीटी की दोपहर 4:45 बजे तीव्रता 5.1 रही। यहां भी किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है। पाकिस्तान में भूकंप: थक्कर की सुबह 5:45 बजे दूसरी भूकंप पाकिस